

नव भारत, भोपाल

6 DEC 2010

सामाजिक सरोकारों पर खर्च नौ फीसदी से अधिक

रिजर्व बैंक की स्टडी में खुलासा

भोपाल, 15 दिसंबर. सामाजिक जरूरतों की अनदेखी कर नए मध्यप्रदेश का खाब कोरा था, इसलिये राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को पिछले प्रांच सालों से भारी तवज्जो दे रखी है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक हालिया अध्ययन के खुलासे में यह तथ्य उकेरा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार का सामाजिक सरोकारों से जुड़े खर्चों का प्रतिशत बढ़कर 9.3 के ग्राफ पर जा पहुंचा है। इस रिपोर्ट की जानकारी का प्रमाण यह है कि प्रदेश में समाज कल्याण से जुड़ी आधा दर्जन से ज्यादा योजनाओं का काम यथार्थ पर आंका जा चुका है.

कैसे शुरू हुई थीं कोशिशें- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक बदलावों में शुरू से ही पिछड़े एवं गरीब तबके से जुड़े सरोकारों को खासा महत्व दे रखा है। आधा दर्जन से ज्यादा योजनाएं जिनमें जननी सुरक्षा एक्सप्रेस, दीनदयाल अंत्योदय उपचार, लाइली-लक्ष्मी, दीनदयाल चलित अस्पताल, गांव की बेटों, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा, कन्यादान आदि शामिल हैं उनका निर्माण और क्रियान्वयन मुख्यमंत्री के इसी इरादे पर केन्द्रित था.

उनकी नये मध्यप्रदेश के निर्माण की सोच को पूरा करने का सिलसिला ही इन योजनाओं के

साथ शुरू हुआ था और इनके बेहतर नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में अपनी बनाई इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये आज भी लोगों को जगह-जगह प्रोत्साहित ही नहीं करते बल्कि उकसाते हैं.

एक दर्जन राज्य पीछे छूटे- रिजर्व बैंक की इस अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक क्षेत्र में राज्य सरकार के बड़े खर्च को प्रदेश के मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में साल 2005-10 के दौरान हुए इजाफे के साथ 9.3 प्रतिशत आंका गया है। रिपोर्ट में हवाले के साथ बताया गया है कि प्रदेश में ही इसके पहले के पांच सालों यानि साल 2000-2005 के दौरान इस खर्च का प्रतिशत 7.5 दर्ज हुआ था.

रिपोर्ट में साफ किया गया है कि प्रदेश में सामाजिक सरोकारों के इस बड़े खर्च के चलते कोई एक दर्जन बड़े राज्य पीछे छूट गए हैं। इनमें इस मद के खर्च की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में यह आँकड़ा 9 प्रतिशत, महाराष्ट्र 5.8, पंजाब 4.4, हरियाणा 4.9, गुजरात 3.1 प्रतिशत तक सिमटा हुआ है. आन्ध्रप्रदेश 7.9, तमिलनाडू 6.7, उड़ीसा 8.4, पश्चिम बंगाल 5.7, गोआ 7.2, केरल 5.8 और कर्नाटक में सामाजिक क्षेत्र की मद में सरकारी खर्च 5.7